units in the sector other than Small Scale Industrie* in the Union Territory of Pondicherry as on 31-12-1988.

For revival of sick industrial units, Union Government have a uniform policy for the country as a whole, which *inter alia,* includes setting up of the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), the guidelines on Reserve Bank of India to the Banks for arresting industrial sickness and rehabilitating sick units, a Margin Money Scheme so as to supplement the efforts of the State Government in reducing the incidence of sickness in the Small Scale Sector, an Excise Relief Scheme for excise loans upto 25 per cent of the overall cost of rehabilitation/modernisation/diversification and setting up of a Small Industries Development Bank of India (SIDBI).

आंगनबाड़ी कर्मकारों का शोषण

1462. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :**

कुमारी चन्द्रिका प्रेम जो केनिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 दिसम्बर, 1990 के एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में "पगार 50 रुपये और काम सूरज निकलने से दिन बदलने तक" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जो कि दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा) सहित संपूर्ण देश में आंगनबाड़ी कर्मकारों और अन्य बाल श्रमिकों और महिलाओं के शोषण से संबंधित है ;

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं और उन्हें उनका वाजिब हक दिलाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) इस स्थिति के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों व अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) जी, हां । आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण नहीं किया जाता । वे अवैतनिक अंशकालिक स्वैच्छिक कार्यकर्ता होती हैं जिनको समुदाय से ही लिया जाता है । उन्हें मानदेय दिया जाता है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है । परन्तु वे अधिक मानदेय की मांग कर रहीं हैं जिस पर सरकार ध्यान दे रही है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भी कर्मचारियों का शोषण नहीं हो रहा । फार्मों में अधिकांश कार्य यांत्रिक उपकरणों द्वारा किया जाता है । जहां आवश्यकता होती है स्टाफ को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं । उनकी सेवा शर्तों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बनाये गये भर्ती नियम लागू होते हैं ।

कारखाना अधिनियम, 1948 बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, राज्य दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जैसे आदि विभिन्न श्रम कानूनों में अन्तर्हित कानूनी उपबंधों का कार्यान्वयन जो बाल श्रमिकों महिला श्रमिकों से संबंधित है, मुख्यत: राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों द्वारा किया जाता है । इन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रवर्तन अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और कानूनी उपबंधों का उल्लघंन करने वाले नियोक्ताओं के विरूद्ध कार्यवाई करते हैं । राष्ट्री बाल श्रम नीति (1987) के अनुसरण में बाल श्रमिक बाहुल्य वाले नौ (9) क्षेत्रों में कामकाजी बच्चों के विकास और कल्याण के लिये परियोजनायें शुरू की गई हैं ।

(ग) श्रमिकों आदि के शोषण अथवा कानूनी उपबंधों के उल्लघंन के संबंध में जब कभी अनियोक्ताओं के विरूद्ध विशेष शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उनकी जांच की जाती है ।

Production of Tritium by Bhabha Atomic Research Centre Scientists

1463. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Scientists at Bhabha Atomic Research Centre are able to produce Tritium in high quantity;

(b) if so, the details thereof with amount spent for the production of Tritium;

(o) whether the said production would take the country to advancement;

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor: and

(e) what are the advantages of tritium gas?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): (a) There is no large scale use of tritium in the peaceful use of atomic energy. Hence no need to produce tritium in large quantities.

(b) to (d) Not applicable.

(e) Tritium has many industrial applications such as its use as radioactive tracer, self luminous light source and its possible applications in fusion power in future.

LITE ultras arrested in Madras

1464. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 11 LTTE ultras have been arrested in Madras recently;

(b) jwhether Government propose to take some drastic action to flush out the ultras; and"

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) 10 LTTE militants were arrested by the State Police of Tamil Nadu in Tiruchi on 30-11-1990.

(b) and (c) The Government of Tamil Nadu have reported that they are taking action to curtail militants' activities in the State. Apart from detaining the militants under National Security Act^ 1986. Sri Lankan Tamil Militants were rounded up both from outside and four refugee camps by State Police recently. They are kept in Special Camps at various places. Action is being taken by the State Police to prevent infiltration of militants into the coastal areas in the State.

Detentions under NSA

1465. SHRI PASUMPON THA KIRUTTINAN:

SHRI V. GOPALSAMY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of people detained under the National Security Act during the last three years in each State, State-wise and year-wise;

(b) whether the detention of people under NSA has helped reduce violence in each State during this period; and

(c) what steps are being taken to restore peace in various parts of the country where violance has become order of the day?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) A statement show-